राजस्थान फ़ाउण्डेशन
Rajasthan Foundation

December, 2010

Rajasthan Foundation Newsletter

राजस्थान फ़ाउण्डेशन पत्रिका

सभी
प्रवासी बन्धुओं को
नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

प्रिय प्रवासी भाइयों और बहनों

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

नया वर्ष आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग लाये ऐसी कामना करता हूँ।

नया वर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर नयेपन का स्वागत करें। राजस्थान की विकास यात्रा इसी विचार को प्रतिबिंबित करती है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव की बेड़ियाँ तोड़कर आज राजस्थान विकास के हर क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है।

हमने एक नये राजस्थान के निर्माण की वचनबद्धता दर्शाते हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की अवधारणा के साथ नवाचारों को महत्त्व दिया है। हमने नई सोच के साथ विकास के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को सामने रखकर समग्र और संतुलित विकास की अवधारणा के साथ ठोस वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध को भी प्राथमिकता दी है।

किसी देश या प्रदेश में विकास के प्रयास तभी सार्थक होते हैं जब प्रत्येक नागरिक को इनका लाभ मिले। हमने राज्य के सर्वांगीण और समेकित विकास का संकल्प लिया है और विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से इसे साकार कर रहे हैं।

आपके राजस्थान में हो रहे चहुँमुखी विकास के बारे में जानकर आप निश्चित ही गर्वोन्नत होंगे।

जनवरी 2012 में प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) जयपुर में आयोजित होगा। मैं आप को आमंत्रित करता हूँ कि आप जयपुर पधारें, हम सभी आप के स्वागत को उत्सुक हैं।

भवदीय
अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

राजस्थान
विकास के नये आयाम

देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान पाने को उत्सुक राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। अल्प समय में लिये दूरदर्शी निर्णयों ने प्रदेश के उन्नत कल की आधार शिला रख दी है।

पर्यटन

पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का सदैव ही अग्रणी स्थान रहा है। राज्य में आने वाले भारतीय व अन्तर्राट्रीय पर्यटकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस दिशा में कई नई पहल की गईं।

- पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से Royal Rajasthan on Wheels नाम से दूसरी पर्यटक रेल जनवरी 2009 से शुरू की गई है।
- जयपुर में The Great Indian Travel Bazar-2009 का सफलतापूर्वक आयोजन 19-21 अप्रेल, 2009 तक किया गया, जिसमें 178 Foreign buyers एवं भारत के 8 राज्यों ने भाग लिया। यह मार्ट भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहला Pan-India अन्तर्राष्ट्रीय Travel Mart है।

पेट्रोलियम

राज्य में पेट्रोलियम की खोज से विकास की अभूतपूर्व सम्भावनायें उभर कर आई हैं।

- केयर्न एनर्जी द्वारा 70 कुओं की खुदाई कर अब तक कुल 202 कुओं की खुदाई की जा चुकी है। कम्पनी द्वारा अब तक 25 तेल फील्ड एवं गैस फील्ड की खोज की गई तथा लगभग 480 मिलियन टन इनप्लेस खनिज तेल के भंडार तथा 3000-6000 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस के इनप्लेस भंडार आंकलित किए गए हैं। मंगला की खोज देश की गत दो दशकों की सबसे बड़ी खोज है।

बाड़मेर में मंगला की खोज गत दो दशकों में खनिज तेल की सबसे बड़ी खोज है।

- राज्य के कोल बेड मीथेन के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के विकास हेतु बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्य किया गया है।
- बीकानेर क्षेत्र में लगभग 950 मिलियन घन मीटर कोल बेड मीथेन के भण्डार मिलने की संभावना है। जिसके दोहन से बीकानेर क्षेत्र में लगभग 5500 मेगावाट के विद्युत संयत्र अथवा 20 टन प्रति दिन क्षमता के यूरिया प्लांट एवं बीकानेर स्थित सिरेमिक इंड्रस्टी को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

उद्योग

राज्य सरकार औद्योगीकरण को आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन का आधार मानती है और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम उठा रही है।

- राज्य में निवेश के लिये एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसके विधिक आधार प्रदान किये जाने हेतु ''राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल प्वाइंट एनेबिलिंग एण्ड क्लीयरेन्स ऑर्डिनेन्स 2010" जारी किया जा चुका है।
- औद्योगिक विकास में वृद्धि हेतु RIICO द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था, जैट्रो के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है जिसके तहत जैट्रो के सहयोग द्वारा राजस्थान के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न जापानी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस प्रयास से बहुराष्ट्रीय जापानी कम्पनियों जैसे निसिन, मित्सुई, डाईकिन, मित्सुबिशी डाईकी कलर आदि ने इकाइयां स्थापित करने के लिये जमीन आवंटित करा ली है।

इस क्षेत्र में 9 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है व 5 इकाइयों में निर्माण कार्य जारी है। अब तक 22 इकाइयों को 305 करोड़ एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी हैं। आवंटित भूमि पर लगभग ₹2260 करोड़ के निवेश की सम्भावना है व इससे 4800 व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

- वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु सिलोरा, किशनगढ़ में भारत सरकार की एस.आई.टी.पी. योजना के तहत दो इन्टीग्रेटेड टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जा रही है। इन परियोजनाओं पर कुल निवेश ₹585 करोड़ अनुमानित है जिनमें 3500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से व 6500 व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
- जयपुर में जनवरी 2009 में इण्डिया स्टोन मार्ट का आयोजन, फिक्की के सहयोग से किया गया। इसमें चीन, तुर्की, इटली, जर्मनी, यू.के., पाकिस्तान, रूस, ओमान आदि देशों के अतिरिक्त भारत के प्रमुख राज्यों द्वारा भी पवेलियन लगाए गये।
- RIICO द्वारा होण्डा सीयल कार इण्डिया, लिमिटेड को खुशखेड़ा, भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र अलवर में कार उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना

माननीय प्रधान मंत्री, श्री मनमोहन सिंह (बीच में) बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए। साथ खड़े है माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत (बाँये)

हेतु 610 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जो राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होगा।

- बहुराष्ट्रीय कम्पनी सेन्ट गोबेन ग्रुप दुनिया की फोरचुन 500 कम्पनियों की सूची में 116वें स्थान पर है जिसकी सहायक कम्पनी सेन्ट गोबेन ग्लास इण्डिया द्वारा भिवाड़ी, जिला अलवर में ₹1000 करोड़ का निवेश कर फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित होगा, जिसके लिये RIICO ने भूमि आवंटित कर दी है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र राज्य में स्थापित होगा।
- नई औद्योगिक एवं निवेश नीति तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना - 2010 जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत देय वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान तथा छूट विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों को राजस्थान में निवेश हेतु आकर्षित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

आधारभूत संरचना

ऊर्जा मजबूत आधारभूत संरचना न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास के लिये भी अत्यन्त महत्त्पूर्ण है।

- राज्य में अधिक से अधिक विनिवेश एवं आधारभूत संरचनाओं, औद्योगिक एवं चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य में पिछले 23 माह में उत्पादन क्षमता में 2285 मेगावाट की वृद्धि हुई है।

राज्य में निवेश के लिये एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसके विधिक आधार प्रदान किये जाने हेतु "राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल प्वाइंट एनेबिलिंग एण्ड क्लीयरेन्स ऑडिनेन्स 2010" जारी किया जा चुका है।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि

- उत्पादन क्षमता को बढावा देने हेतु, राज्य सरकार ने 3 नये सुपर क्रिटिकल ताप बिजलीघर छबड़ा, सूरतगढ़ और बांसवाड़ा में स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इन बिजलीघरों की क्षमता 3 हजार 960 मेगावाट होगी तथा इनके निर्माण पर ₹23 हजार 760 करोड़ खर्च होंगे। सूरतगढ एवं छबड़ा की परियोजनाएं राज्य क्षेत्र में तथा बांसवाड़ा परियोजना निजी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है इन पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 12000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है जिससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत (बाँये) व उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक होन्डा टू-व्हीलर संयंत्र के शिला पट्ट का अनावरण करते हुए

चालू परियोजनाएं

- 2X250 मेगावाट छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना (यूनिट 3 व 4) तथा 2X660 मेगावाट कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा इन इकाइयों से क्रमशः अक्टूबर-दिसम्बर 2011 तथा दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 की अवधि में उत्पादन प्रारम्भ होना संभावित हैं।
- उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु रामगढ़ (जैसलमेर) में तृतीय चरण के अन्तर्गत 160 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित तापीय विद्युतगृह स्थापित करने की स्वीकृति दी गई हैं। इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 110 मेगावाट क्षमता की गैस टरबाईन इकाई नवम्बर 2011 तथा 50 मेगावाट की स्टीम टरबाईन इकाई से

मार्च 2012 में उत्पादन प्रारम्भ करना संभावित हैं।

- गिरल (बाड़मेर) में 2X125 मेगावाट (यूनिट 3-4, स्टेज-III) लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युतगृह को राज्य क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु गिरल परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाई के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अब इस परियोजना की तृतीय एवं चतुर्थ इकाई को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया केस-2 के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा। इस कार्य हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में लगाये जाने वाले 4780 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युत गृहों की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई हैं। इनमें से 4450 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युत गृहों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

राज्य में पिछले 23 माह में विद्युत उत्पादन क्षमता में 2285 मेगावाट की वृद्धि हुई है।

ग़ैर परम्परागत ऊर्जा

मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति मुख्यालय में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के संचालन के लिये स्थापित किये जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का अवलोकन करते हुए

- राज्य सरकार ग़ैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। 467.5 मेगावाट क्षमता की पवन एवं बायोमास परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। वर्ष 2010-11 में 300 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं तथा 28 मेगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। बायोमास से विद्युत उत्पादन को बढावा देने हेतु बायोमास नीति, 2010 जारी की गई है।
- राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा की 66 मेगावाट क्षमता की 11 निजी कम्पनियों की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं को जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

सड़क

- जयपुर-कोटपूतली-गुडगांव के 6 लेन-मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- सड़कों के विकास पर ₹3910.57 करोड़ का व्यय किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2042 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 250 व इससे अधिक आबादी के 626 गावों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 676 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 112 धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ा गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 250 व इससे अधिक आबादी के 856 गाँवों को तथा 250 से कम आबादी के जनजाति क्षेत्रों में 50 व मरू क्षेत्रों में 190 गाँवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ा गया है।
- 789 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है।
- राजस्थान पहला राज्य है जिसने सड़क सुविधाओं के विकास के लिये PPP एवं BOT पद्धति अपनाई है। राज्य में अब तक 2164 कि.मी. लम्बाई की ₹2118 करोड़ की लागत से 40 सड़क परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। राज्य में सड़को के विकास के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हुए एक वृहद् योजना बी.ओ.टी., पी.पी.पी., टोल, वी.जी.एफ. एवं सूओमोटो आधार पर तैयार की गई हैं।
- वर्ष 2010-11 में लगभग 4835 कि.मी. लम्बाई की 51 परियोजनाएं प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें लगभग ₹8461 करोड़ का विनिवेश होना संभावित है।
- 1378 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय उच्च मार्गो को ₹4306 करोड़ की लागत से पीपीपी आधार पर वीजीएफ के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए 11 परियोजनाओं को चिह्नित कर लिया गया है। 11 परियोजनाओं के प्रतिवेदन की फिजीबिलीटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा 9 परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं।

नगरीय विकास

- जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (JNNURM) राज्य के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत चयनित किया गया है। इन शहरों के आधारभूत विकास की एवं शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाओं की 15 परियोजनायें

मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में मेट्रो रेल परियोजना के लिये एम.ओ.यू. करते हुए अधिकारी

₹1567.30 करोड़ की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी हैं। इस योजनान्तर्गत अब तक कुल ₹673.69 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से ₹566.32 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

- लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु आधारभूत विकास योजना (UIDSSMT): भारत सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम क्षेत्रों के कस्बों का आधारभूत विकास हेतु अब तक ₹609.93 करोड़ की 37 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी रूफडिको के माध्यम से कार्य प्रगति पर है।

आम आदमी को सस्ती दर पर आवास मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 बनाई गई।

- इन्टीग्रेटिड हाउसिंग एंड स्लम डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹641.87 करोड़ की स्वीकृत 46 परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है।
- राष्ट्रीय झील संरक्षण योजनान्तर्गत पिछोला झील, फतेहसागर झील (उदयपुर) आनासागर झील (अजमेर) एवं पुष्कर, झीलों के संरक्षण एवं विकास की परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- वर्ष 2012-13 तक राज्य के 109 शहरों के मास्टर प्लान बनाने की योजना अन्तर्गत 21 शहरों के मास्टर प्लान जारी किये जा चुके हैं, 13 शहरों के मास्टर प्लान तैयार कर लिये गये है। शेष 74 शहरो के नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं।
- आम आदमी को सस्ती दर पर आवास मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 बनाई गई। अभी तक जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भिवाड़ी, चाकसू, कुचामनसिटी व दौसा में स्वयं की भूमि पर आवास बनाकर आंवटित करने हेतु 15 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि 12 हजार 140 आवासों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है।
- राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 जारी की गई।
- जयपुर मैट्रो परियोजना के लिए एक कम्पनी का गठन किया जा चुका है। प्रथम फेज में मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो के कोरिडोर के लिए निर्माण हेतु डी.एम.आर.सी से MOU साईन किया गया है। डी.एम.आर.सी. द्वारा निविदाये आमंत्रित की गई है।
- राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ₹400 करोड़ का शहरी विकास कोष स्थापित किया गया है।
- राज्य के 20 शहरों - अलवर, अजमेर, बारां, ब्यावर, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, झालावाड़, झालरापाटन, जैसलमेर, करौली, मकराना, नागौर, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं उदयपुर - में 1061.28 करोड़ रुपयों के जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।
- शहरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक शहर का सिटी डवलपमेन्ट प्लॉन (सीडीपी) बनाने का निर्णय लिया गया है और 25 सीडीपी बनाये जा चुके हैं।
- 16 शहरों में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट हेतु ₹46.51 करोड़ के कार्य किये जा रहे है। यही कार्य अन्य शहरों में भी कराये जाएंगे।
- राजीव आवास योजना के तहत 15 अगस्त, 2009 तक कच्ची बस्ती में बसे परिवारों का समस्त शहरों में सर्वे करवाया जा रहा है ताकि कच्ची बस्ती नियमन में विकास के सम्बंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति की जा सके।
- राज्य की राजधानी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की स्थापना की गई है एवं ₹142.82 करोड़ की लागत से 400 लो-फ्लोर बसें चलाने की योजना है। इसके अन्तर्गत 220 बसें खरीदी जा चुकी हैं और 190 लो-फ्लोर बसें चल रही है।
- शहरी क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) हेतु नगरीय निकायों के अधिकार बढ़ाये गये, जिससे त्वरित गति से स्वीकृतियां जारी हो सकें।
- जयपुर में 49 किलोमीटर की लम्बाई की ₹479 करोड़ की लागत से बी.आर.टी.एस. योजना का कार्य प्रगति पर है। इसके तहत 7.1 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लो-फ्लोर बसें चलाई जा रही हैं।

सामाजिक क्षेत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेज में स्वाईन फ्लू निदान हेतु अत्याधुनिक लैबोरेट्री स्थापित कर दी गई है। बी.पी.एल. वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं को स्वाइन फ्लू का टीका निःशुल्क लगाने का भी निर्णय लिया है। इस पर ₹2.50 करोड़ की राशि व्यय होगी।

मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

- जयपुर में एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेमसैल प्रयोगशाला प्रारंभ कर दी गयी है।
- एस.एम.एस. में 12 ऑपरेशन थियेटर्स को आरम्भ करने हेतु उपकरण क्रय कर लिये गये हैं। 7 नये ओ.टी. प्रारम्भ कर दिये गये है एवं शेष शीघ्र ही प्रारंभ कर दिये जायेंगे।
- गम्भीर मरीज एवं दुर्घटना ग्रस्त रोगी को तत्काल एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 108 एम्बूलेंस की लोकप्रियता को देखते हुए 150 नई एम्बूलेंस जोड़ी गई। अब अब तक राज्य में कुल 314 एम्बूलेंस नियोजित हैं।
- आमजन को सस्ती दर पर दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु 'जन-औषधि केन्द्रों' का शुभारम्भ किया गया।
- मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत 55.80 लाख गरीबों को ₹53.87

करोड़ की निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

- बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के साथ एचआईवी पीडित व वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, पेंशनरों, सहरिया, आस्थाकार्ड धारी एवं अंत्योदय अन्न योजना, नवजीवन योजना और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी को पूर्णतः निःशुल्क इण्डोर/आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्राईमरी हैल्थ वर्कर (स्वास्थ्य मित्र) तथा एक ए.एन.एम. की नियुक्ति की जायेगी, इसके लिए राज्य योजनान्तर्गत मद में 2500 अतिरिक्त ए.एन.एम. पद राज्य योजना मद से एवं 2500 ए.एन.एम. के पद एन.आर.एच.एम. से सृजित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिसमें से 4770 अतिरिक्त ए.एन.एम. को नियुक्ति दी जा चुकी है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 537 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

शिक्षा

- भारत सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षा के अधिकार के ऐतिहासिक कानून को पूरे राज्य में लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। शिक्षा के अधिकार के कानून को राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जा रहा है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस कानून के अनुरूप किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक स्कूल तक जाने के 1 कि.मी., उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 कि.मी. तथा माध्यमिक विद्यालय तक जाने में 5 से 7 कि.मी. की परिधि से बाहर नहीं जाना पड़े। इसके विभिन्न प्रावधानों को राज्य में लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

आमजन को सस्ती दर पर दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु 'जन औषधि केन्द्रों' का शुभारम्भ किया गया।

राज्य के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करते विद्यार्थी

- राज्य की सभी बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है, ताकि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर होने वाले 14 प्रतिशत ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित किया जा सके।
- राज्य के प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा हेतु 1892 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया है। इससे अधिक से अधिक बालिकाएं माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने पंचायत क्षेत्र के अंदर ही प्राप्त कर सकेंगी।
- राज्य के 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।
- साक्षरता एवं सतत शिक्षा के अंतर्गत विशेष महिला शिविर आयोजित कर 99 हजार 204 महिलाओं को साक्षर किया गया, इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 401 व्यावसायिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये, जिनमें 20 हजार 60 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।
- राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों के 6 हजार 147 विद्यालयों में लहर (Learning Enhancement Activity in Rajasthan) कार्यक्रम संचालित है एवं सत्र 2010-11 के लिए 4436 नये लहर स्कूल चयनित किये गये।
- विज्ञान विषय को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारम्भ इंस्पायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत 19413 विद्यार्थियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। पूरे देश में राजस्थान राज्य का स्थान प्रथम रहा है।

उच्च शिक्षा

- राजकीय महाविद्यालयों में 212 नये वर्ग स्वीकृत किये गये हैं, प्रत्येक वर्ग 80 से बढ़ाकर 100 सीटें की गई हैं एवं इससे 25 हजार छात्र लाभान्वित होंगे।
- युवाओं के विकास व उन्हें रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध मे सहायता देने के लिए सभी 126 राजकीय महाविद्यालयों में 122 युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ किए

गए हैं। इसके लिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय को ₹1 लाख का बजट आवंटित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किशनगढ़ (अजमेर) में की जा रही है।
- निजी क्षेत्र में 18 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये तथा 282 निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति पत्र जारी किये गये।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस कानून के अनुरूप किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक स्कूल तक जाने में 1 कि. मी., उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 कि.मी. तथा माध्यमिक विद्यालय तक जाने में 5 से 7 कि.मी. की परिधि से बाहर नहीं जाना पड़े।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ₹1993.24 करोड़ प्राप्त कर ₹1865.99 करोड़ व्यय किये गये।
- बंजर भूमि के विकास हेतु "वेस्ट लैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड" का गठन किया गया है।
- इंदिरा आवास योजना में गरीब परिवारों के लिए 131507 नये आवास बनाये गये हैं तथा 5869 अर्द्ध निर्मित एवं कच्चे आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत किया गया है।
- वर्ष 2008-09 से अनुसूचित जाति के बीपीएल चयनित आवासहीन परिवारों को कुल ₹ 50,000 प्रति आवास अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान सहायता ₹15,000 प्रति आवास शामिल है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹85.49 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि जारी कर 55212 परिवारों को आवास स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया।

महिला विकास

- प्रसूताओं को कलेवा योजनान्तर्गत प्रसूता महिलाओं को प्रथम दो दिवस तक संस्थागत प्रसव कराने पर गरम भोजन 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिया जाता है। यह राष्ट्र में एक अभिनव प्रयोग है।

राज्य सरकार निरन्तर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विभिन्न कार्य कर रही है

मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत पाली जिले में मामावास मार्ग पर नरेगा के तहत चल रहे ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य स्थल का अवलोकन करते हुए

- सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रति जोड़ा देय अनुदान राशि ₹5000 से बढ़ाकर ₹6000 की गई। न्यूनतम जोड़ों की संख्या 10 है। अधिकतम अनुदान की राशि ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई है। जोड़े को देय अनुदान राशि में से 25 प्रतिशत आयोजनकर्ता को एवं 75 प्रतिशत राशि वधू के बैंक खाते में जमा करवाने की व्यवस्था लागू की गई है तथा 2630 जोड़ों को लाभान्वित किया गया है।
- राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

निजी क्षेत्र में 18 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये तथा 282 निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति पत्र जारी किये गये।

Jaipur to host PBD 2012

Government of Rajasthan will host the 10th edition of Pravasi Bharatiya Divas (PBD). The convention will be held in the beautiful pink city, Jaipur — now also one of the fastest growing cities in India — from 7th to 9th January 2012.

PBD is celebrated every year to mark the contribution of overseas Indian community in the development of India. January 9 was chosen as the day to celebrate this occasion since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, returned to India from South Africa, led India's freedom struggle and changed the lives of Indians forever.

PBD conventions are being held every year since 2003. These conventions provide a platform to the overseas Indian community to engage with the government and people of the land of their ancestors for mutually beneficial activities. PBD is organised by the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India the Confederation of Indian Industry as the institutional partner.

It was Government of Rajasthan that had taken the initiative to connect with the diaspora way back in the year 2000, three years before the first PBD. The International Rajasthani Conclave (IRC 2000) held in Jaipur had marked the beginning of a new chapter in the relationships between the non-resident Rajasthanis and the state of their origin.

Work starts on Jaipur Metro

The Rajasthan Government has finalised a ₹7,500-crore Jaipur Metro Rail project, as part of its bid to make Jaipur a world-class city.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) was given the task to prepare a detailed project report (DPR) for the city, which has a population of nearly half a crore. After carrying out a survey for nearly for six months, DMRC officials have submitted their report to the State Government.

The first route (east-west corridor) will connect Mansarovar to Badi Chaupar via Civil Lines and Chandpole. This 9.5 km route is expected to carry 2 lakh passengers every day. The second route of Jaipur metro rail will connect Durgapura to Ambabari via Ajmeri Gate and MI Road. Part of this 23 km track will be elevated and the remaining, underground. This route is likely to cater to 4 lakh passengers every day.

According to the DPR, total length of the proposed Metro train route would be about 29 km, comprising of two corridors - east and west. The State Government has already formed a company, Jaipur Metro Corporation to implement the project, with Urban and Housing Principal Secretary, Mr GS Sandhu as CMD of the company. Government of India and the State Government each, are expected to provide 20 per cent of the funding.

The pile test work that will help the engineers to calculate the load-bearing capacity of the ground and design a suitable foundation for the track has commenced. The Metro is scheduled to perform the test run by March 2013, while the revenue operations will commence from November 1, 2013.

वैबपोर्टल पर निःशुल्क सदस्यता की सुविधा

राजस्थान फ़ाउण्डेशन समस्त प्रवासी राजस्थानी बन्धुओं से आग्रह करता है कि वे फ़ाउण्डेशन के वेबपोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सदस्य बनें जिससे वे राज्य एवं फ़ाउण्डेशन की गतिविधियों से समय-समय पर अवगत हो सकें।

Rajasthan Foundation looks forward to hearing from you. Kindly get in touch with us at:
Rajasthan Foundation, Yojana Bhawan, Yudhishthir Marg, C-Scheme, Jaipur 302005, Rajasthan, India.
Tel: +91 141 2229091, Commissioner (Direct): +91 141 2229111,
Executive Director (Direct): + 91 141 2229444, Fax: +91 141 5113224
E-mail: rajfound-rj@nic.in www.rajasthanfoundation.org

Layout by MERCURY | Printed at Kumar & Co. | December 2010 | For Private Circulation